माननीय न्यायमूर्ति जी. सी. मित्तल के समक्ष

राम मेहर बनाम सूरत सिंह एवं अन्य

रेगुलर सेकंड अपील न. 2322 ऑफ 1988

30 मार्च, 1989

1. एक प्रतिनिधि मामले में, गांव गढ़ी सांपला के आबादी देह के विभाजन के लिए प्रारंभिक डिक्री 23 फरवरी, 1981 को उप-न्यायाधीश प्रथम श्रेणी, रोहतक द्वारा पारित की गई थी। न्यायालय ने प्रारंभिक डिक्री पारित करते हुए श्री एसएस दहिया, वकील को नियुक्त किया। भूमि के विभाजन के लिए स्थानीय आयुक्त के रूप में। हालाँकि, बाद में उस स्थानीय आयुक्त को हटा दिया गया और श्री विजय सिंह सेवानिवृत्त तहसीलदार को प्रारंभिक डिक्री के अनुसार विभाजन का प्रस्ताव देने के लिए स्थानीय आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया। उन्होंने आबादी भूमि के विभाजन का सुझाव देते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसके खिलाफ कुछ सह-हिस्सेदारों ने लिखित आपत्तियां दायर कीं।

2. 14 अक्टूबर 1985 को आपत्तिकर्ताओं और/या उनके अधिवक्ताओं ने न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित आशय का संयुक्त बयान दिया:

हम इस बात पर सहमत हैं कि श्री सुल्तान सिंह दहिया, एडवोकेट, रोहतक को 'सूरत सिंह बनाम केहरी' मुकदमे में आपत्तियों और किसी अन्य विवाद पर निर्णय लेने के लिए इस मामले में रेफरी नियुक्त किया जाए। वह जो भी निर्णय लेंगे वह सभी पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। वह स्थानीय आयुक्त की रिपोर्ट में आवश्यक संशोधन करने के लिए अधिकृत होंगे।"

न्यायालय ने निम्नलिखित आदेश पारित किया:

"पक्षकारों और वकील के उपरोक्त बयान के मद्देनजर, श्री सुल्तान सिंह दहिया, अधिवक्ता, रोहतक को इस मामले में रेफरी के रूप में नियुक्त किया जाता है। पक्ष उनके निर्णय से बाध्य होंगे।"

3. 'जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, मुकदमा प्रतिनिधि क्षमता में था और विभाजन के मुकदमे में शामिल कुल शेयर धारकों की संख्या 248 थी। केवल पांच व्यक्ति सिविल पीसी के आदेश 1, नियम 8 के तहत उनका प्रतिनिधित्व कर रहे थे (इसके बाद इसे कहा जाएगा) । कोड). जो भू-स्वामी प्रस्तावित विभाजन से संतुष्ट नहीं थे, उन्होंने या तो इस आधार पर आपत्ति दर्ज की कि उन्हें गलत तरीके से उनके हिस्से की भूमि के आवंटन से वंचित कर दिया गया था, या उन्हें आवंटित भूखंड से अलग भूखंड आवंटित किया जाना चाहिए था। रेफरी ने स्थानीय आयुक्त द्वारा प्रस्तावित आवंटन में परिवर्तन किए जो मौलिक प्रकृति के थे क्योंकि कुछ आवंटियों को वैकल्पिक भूखंड दिए बिना आवंटन से वंचित कर दिया गया, कुछ का क्षेत्रफल कम कर दिया गया और कुछ मामलों में नए भूखंड आवंटित किए गए। जो व्यक्ति परिवर्तनों से प्रभावित थे, उन्हें रेफरी द्वारा सुनवाई का अवसर नहीं दिया गया। यहां तक कि ट्रायल कोर्ट ने रेफरी नियुक्त करने और उसके निर्णय से पक्षों को बाध्य करने के सुझाव को स्वीकार करने से पहले जमीन मालिकों को नोटिस जारी नहीं किया। रेफरी की रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी ट्रायल कोर्ट ने सभी भूमि मालिकों को नोटिस जारी नहीं किया और 14 अक्टूबर, 1985 को दिए गए बयान और रिपोर्ट के आधार पर उनकी रिपोर्ट को पार्टियों के लिए बाध्यकारी माना। रेफरी द्वारा प्रस्तुत अंतिम डिक्री पारित की गई।

4. जब प्रभावित भूस्वामियों को रेफरी की रिपोर्ट के आधार पर पारित अंतिम डिक्री के बारे में पता चला, तो उन्होंने जिला न्यायालय के समक्ष अलग-अलग अपील दायर की, जिन्हें अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ जोड़कर निस्तारित कर दिया गया। समझौता दिनांक 14-10-1985 रेफरी नियुक्त किया गया था और पक्ष उसके निर्णय से बंधे

होने के लिए सहमत हुए थे और रेफरी द्वारा ऐसा निर्णय एक मुकदमे से समझौता करने के अलावा और कुछ नहीं है और उस पर पारित डिक्री एक सहमति डिक्री के समान होगी जो अपील के अधीन नहीं होगी। , और इस प्रकार अपीलों को अक्षम मानकर खारिज कर दिया गया। इसके लिए उन्होंने सूरजभान बनाम जोगी राम , एआईआर 1972 पुंज और हर 398 पर भरोसा किया।

5. अभी भी व्यथित महसूस करते हुए, प्रभावित भूस्वामियों ने: 1988 की आरएसए संख्या 2322, 2323, 2585, 2787 और 2857 दायर की है। चूंकि वे एक ही मुकदमे से उत्पन्न हुए हैं और सामान्य प्रश्न शामिल हैं, इसलिए उन्हें इस सामान्य निर्णय द्वारा निपटाया जा रहा है।

6. संहिता के आदेश 1, नियम 8 के आधार पर जहां समान हित रखने वाले बहुत से व्यक्ति हों, ऐसे व्यक्तियों में से एक या अधिक व्यक्ति न्यायालय की अनुमति से मुकदमा कर सकते हैं या मुकदमा दायर कर सकते हैं, या उनकी ओर से ऐसे मुकदमे का बचाव कर सकते हैं। इस प्रकार के हितबद्ध व्यक्तियों के लाभ के लिए, और जहां अनुमति दी गई है, यह न्यायालय का दायित्व है कि वह इस प्रकार प्रदान किए गए तरीके से सभी हितबद्ध व्यक्तियों को मुकदमे की सूचना दे ताकि उन्हें इसकी संस्था के बारे में पता चल सके। मुकदमा और उनमें से सभी या उनमें से कुछ को रुचि महसूस हो तो वे मुकदमे में पक्षकार बनने के लिए न्यायालय में आवेदन कर सकते हैं।

7. आम तौर पर किसी पक्ष को दावे का कुछ हिस्सा छोड़ने या मुकदमा वापस लेने का अधिकार होता है। एक पक्ष को आदेश 23, नियम 1 और 3 के प्रावधानों के आधार पर समझौते में प्रवेश करने या मुकदमे में पूर्ण या आंशिक रूप से समझौता करने या न्यायालय के आदेश द्वारा दर्ज मुकदमे में दावे की संतुष्टि के लिए सहमत होने का भी अधिकार है। कोड. लेकिन जब कोई मामला प्रतिनिधि क्षमता में दायर किया जाता है या प्रतिनिधि क्षमता में बचाव किया

जाना है, तो आदेश 1 का उप-नियम (4), नियम 8 एक अपवाद बनाता है कि किसी मुकदमे में दावे के हिस्से को छोड़ने की अनुमति नहीं है, और कोई मुकदमा नहीं जब तक न्यायालय उप-नियम (2) में निर्दिष्ट तरीके से सभी इच्छुक व्यक्तियों को नोटिस नहीं देता है, तब तक इसे वापस लिया जा सकता है, न ही उपरोक्त प्रावधानों के तहत कोई समझौता, समझौता या संतुष्टि दर्ज की जा सकती है, इस प्रावधान को बनाने का कारण स्पष्ट था। एक या अधिक व्यक्ति बड़ी संख्या में व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं और यदि लड़ाई का कारण सामान्य है तो वह सभी की ओर से लड़ सकते हैं, लेकिन जब दावे के हिस्से को छोड़ने या मुकदमा वापस लेने या समझौते में प्रवेश करने का सवाल उठता है, तो समझौता या संतुष्टि उत्पन्न होती है। , इसकी अनुमति केवल तभी दी जा सकती है जब सभी सहमत हों, अर्थात, न केवल वे प्रतिनिधि जिन्हें मुकदमा करने या मुकदमा चलाने की अनुमति है, बल्कि मुकदमे में सभी इच्छुक व्यक्ति भी सहमत हैं।

8. यह स्थापित कानून है कि बंटवारे के मुकदमे में सभी पक्ष वादी और प्रतिवादी होते हैं और एक भी पक्ष के बिना न तो मुकदमा आगे बढ़ सकता है और न ही मामले का निपटारा हो सकता है। बँटवारे में शृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया होती है और जैसे ही शृंखला एक स्थान पर टूटती है, मामला सुलझ नहीं पाता।

9. प्रतिनिधि वादों में, ठीक इसी कारण से उप-नियम (4) जोड़ा गया था ताकि पूरे निकाय का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्ति उप-नियम (2) के तहत मुकदमे की सूचना मिलने के बाद गुण-दोष के आधार पर मुकदमा जारी रख सकें।) लेकिन जैसे ही उप-नियम (4) में उल्लिखित किसी भी चीज़ को पूरा करने की मांग की गई, सभी इच्छुक व्यक्तियों, इस मामले में अन्य सह-हिस्सेदारों को फिर से नोटिस जारी करना पड़ा। इस मामले में उप-नियम (4) में निहित प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का पालन नहीं किया गया और जिस दिन रेफरी की नियुक्ति के लिए सुझाव दिया गया, उस दिन न्यायालय ने सुझाव स्वीकार कर लिया और सभी इच्छुक

व्यक्तियों को नोटिस जारी किए बिना रेफरी नियुक्त कर दिया, जैसा कि उप-नियम द्वारा अपेक्षित था। -नियम (4) ऐसा करने में विफलता रेफरी की नियुक्ति के आदेश और उसके बाद की सभी कार्यवाही को रद्द कर देगी।

10. प्रतिवादियों की ओर से डॉ. इकबाल हसन खान बनाम तृतीय अपर. जिला न्यायाधीश, अलीगढ़, एआईआर 1984 सभी 259 का हवाला इस आशय से दिया गया था कि अंतरिम राहत देने के लिए उप-नियम (4) में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने उस मामले के तथ्यों का अध्ययन किया है जो वर्तमान मामले के तथ्यों से स्पष्ट रूप से भिन्न हैं। वहां, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन के चुनाव को चुनौती देने की मांग की गई और अंतरिम व्यवस्था के तहत अदालत की निगरानी में सहमति के अनुसार नए सिरे से चुनाव कराने का आदेश पारित किया गया। कोर्ट ने समझौते को स्वीकार कर लिया और नये सिरे से चुनाव कराने का आदेश दिया. यहां संयुक्त भूमि में पार्टियों के अधिकार शामिल हैं और रेफरी द्वारा उनकी पीठ पीछे लिए गए निर्णय के आधार पर अपीलकर्ताओं को उनके हिस्से से पूर्ण या आंशिक रूप से वंचित किया गया है। यहां तक कि उनकी पीठ पर रेफरी की नियुक्ति का भी आदेश दिया गया है, इसके अलावा, सभी अपीलकर्ता स्थानीय आयुक्त विजय सिंह द्वारा प्रस्तावित विभाजन से खुश थे, और यदि उस रिपोर्ट में छेड़छाड़ की जानी थी तो प्रभावित व्यक्तियों की बात सुनी जानी थी। आपत्तिकर्ता और जिन व्यक्तियों को अन्य सह-हिस्सेदारों का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी गई थी, वे न्यायालय से निर्धारण प्राप्त किए बिना रेफरी के निर्णय से बंधे होने के लिए सहमत हुए। इसीलिए एक प्रतिनिधि मुकदमे में, जबकि एक पक्ष अपील के अधीन गुण-दोष के आधार पर न्यायालय के निर्णय से बाध्य होगा, मुकदमे में रुचि रखने वाले व्यक्तियों के एक बड़े समूह का प्रतिनिधित्व करने वाले व्यक्तियों को समझौता करने या विवाद को निपटाने की शक्ति नहीं दी गई है।

11. सूरजभान के मामले (एआईआर 1972 पुंज और हर 398) (सुप्रा) में दिए गए प्रस्ताव पर कोई विवाद नहीं है , लेकिन यह निर्णय मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होता है, जहां मुकदमे के सभी पक्ष सहमत होते हैं रेफरी की नियुक्ति और उसके निर्णय से बाध्य होने के लिए सहमत होना, रेफरी के निर्णय के आधार पर पारित डिक्री सहमति डिक्री के बराबर हो सकती है; यहां आदेश 1 के उप-नियम (4), संहिता के नियम 8 में सभी इच्छुक व्यक्तियों को नोटिस जारी करने का प्रावधान है, यदि मुकदमे का निर्णय रेफरी द्वारा किया जाना था और पार्टियों को उसके निर्णय से बाध्य होना था। ऐसा नहीं किये जाने पर, रेफरी की नियुक्ति पर कोई सहमति नहीं थी क्योंकि सभी इच्छुक व्यक्तियों द्वारा रेफरी के निर्णय से बाध्य होने का समझौता किया गया था। इसलिए, निचली अपीलीय अदालत और इस अदालत के समक्ष अपील स्पष्ट रूप से विचारणीय है।

12. ऊपर दर्ज कारणों के लिए, अपील की अनुमति दी जाती है और ट्रायल कोर्ट का आदेश दिनांकित है। 14-10-1985, श्री एसएस दहिया, अधिवक्ता, रोहतक को रेफरी के रूप में नियुक्त किया गया और उसके बाद उनके द्वारा और ट्रायल कोर्ट द्वारा की गई सभी कार्यवाही को रद्द कर दिया गया और मामले को ट्रायल कोर्ट में भेज दिया गया ताकि मामले को चरण से आगे बढ़ाया जा सके। स्थानीय आयुक्त के रूप में सेवानिवृत्त तहसीलदार विजय सिंह की रिपोर्ट के खिलाफ आपत्तियां प्राप्त करने और कानून के अनुसार आगे बढ़ने के लिए।

13. यदि स्थानीय आयुक्त विजय सिंह द्वारा प्रस्तावित विभाजन में परिवर्तन करना आवश्यक हो जाता है, तो ऐसा करने से पहले प्रभावित व्यक्तियों की सुनवाई की जाएगी। हालाँकि, पार्टियों को अपनी लागत स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया गया है।

14. पक्षों को अपने वकील के माध्यम से 22-5-1989 को ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए हैताकि वह अपनी भाषा में इसेसमझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

मंदीप सिंह

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी (Trainee Judicial Officer) Gurugram, हरियाणा